राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4489/2024

1. पूरा राम पुत्र जूथ राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी-गोमती नदी के पास, भीनमाल, जिला। जालोर, राज.

2. अशोक पुत्र अगरा जी उर्फ इगाजी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी गोमती नदी के पास, भीनमाल, जिला। जालोर, राज.

3. मेहेन्द्र पुत्र रेखा जी, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी-गोमती नदी के पास, भीनमाल, जिला। जालोर, राज.

4. लाला राम पुत्र मसा राम जी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी-गोमती नदी के पास, भीनमाल, जिला। जालोर, राज. ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से।

2. बाबूराम पुत्र सवाजी, निवासी मेघवालों का मौहल्ला, जगजीवन राम कॉलोनी, भीनमाल, थाना भीनमाल, जिला. जालोर, राज.----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री अभिमन्यु सिंह राणावत।

प्रतिवादी के लिए: श्री विक्रम शर्मा, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

15/07/2024

1. याचिकाकर्ता/आरोपी इस न्यायालय के समक्ष धारा 302, 306, 201, और 34 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन भीनमाल, जिला जालोर में दर्ज एफआईआर संख्या 266/2024, दिनांक 27.06.2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

2. संक्षेप में, याचिका से संबंधित तथ्य पहले। शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने एसीजेएम, भीनमाल के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 26.09.2023 को, उसका बेटा जयरूपाराम, उम्र 25 वर्ष, मजदूरी के काम के लिए भीनमाल गया था, लेकिन उस रात घर नहीं लौटा। 27.09.2023 को, शिकायतकर्ता को सूचना मिली कि गोमती नाडी में एक शव मिला है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शव की पहचान की, जिसे भीनमाल अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी, जो पहले उसके बेटे के साथ काम करता था और शुरू में उसके साथ अच्छे संबंध थे, बाद में उससे दूर हो गए। आरोपी ने इस घटना से पहले कथित तौर पर उसके बेटे के साथ तीन-चार बार मारपीट की थी। आरोप है कि आरोपी ने किसी तरह से उसके बेटे की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। इन आरोपों के आधार पर संबंधित एफआईआर दर्ज की गई।

3. इस संदर्भ में मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि एफआईआर में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है और एफआईआर केवल याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए दर्ज की

गई है। एफआईआर दर्ज करने में 9 महीने की देरी को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता के बेटे और याचिकाकर्ताओं के बीच किसी भी स्पष्ट विवाद के बिना एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने खुद दुख और अवसाद में होने की बात स्वीकार की है। इसलिए, एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी वकील का तर्क है कि जांच अभी भी जारी है और इस प्रक्रिया के दौरान सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका कहना है कि केवल याचिका/शपथपत्र की सामग्री के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है, जिसकी अभी जांच होनी है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुनने और केस फाइल और एफआईआर की सामग्री की समीक्षा करने के बाद, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क और याचिका में लिए गए सभी आधार तथ्यात्मक दावे हैं। एफआईआर में कानून में कोई कमी, अवैधता या अनियमितता नहीं बताई गई है, जिसे पढ़ने पर यह नहीं पता चलता कि आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, जिसके लिए इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

7. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, एफआईआर की सामग्री को पढ़ने पर यह संकेत मिलना चाहिए कि न्यायालय में आने वाले आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

8. वर्तमान मामले में, एफआईआर से ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जो इसे रद्द करने का औचित्य सिद्ध करे। जांच और सुनवाई के दौरान सच्चाई सामने

आ जाएगी, और इस न्यायालय के लिए इस प्रारंभिक चरण में एफआईआर की सत्यता पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

9. आरोपों की प्रकृति और एफआईआर में दर्ज बयान को देखते हुए, जो गंभीर हैं, इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। 25 साल के एक युवक की मौत हो गई, और सच्चाई को उजागर करने के लिए जांच की जानी चाहिए।

10. जब तक चल रही कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों, तब तक रद्द करने की याचिका की अनुमति देना उचित नहीं है। वर्तमान मामले के तर्कों, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं इस राय पर हूँ कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

11. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा लिया गया रुख उचित प्रतीत होता है।

12. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है कि याचिकाकर्ता कानून के तहत अपना उपाय तलाश सकते हैं, जो जांच पूरी होने के बाद सक्षम अदालत के समक्ष उचित चरण में उनके लिए उपलब्ध हो सकता है।

13. इस प्रकार याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने को एफआईआर में लगाए गए आरोपों के पक्ष या विपक्ष में योग्यता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। जांच एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी, यहां की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, जो केवल तत्काल याचिका के निपटान के उद्देश्य से हैं।

14. मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ताओं को उचित स्तर पर सक्षम न्यायालय के समक्ष अपना पूरा बचाव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलें भी शामिल हैं, जो निर्णय के लिए खुली रहेंगी।

(अरुण मोंगा), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।